

Andhra Bank Where India Banks Inspection & Audit Department Head Office Koti Building 4th Floor Sultan Bazar, Hyderabad - 500 095.Ph: 2468 3402/2468 3406 Email: ravirama@andhrabank.co.in; isaudit@andhrabank.co.in

BHARAT ELECTRONICS LIMITED (A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence) Registered Office: Floor No. 3, DHFLVC Silicon Towers, Kondapur, Hyderabad - 500084

JAGRAN PRAKASHAN LIMITED Corporate Identity Number: L22219UP1975PLC004147 Registered Office address: Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208005; Website: www.jplcorp.in

Indiabulls REAL ESTATE Indiabulls Real Estate Limited (CIN: L45101DL2006PLC148314) Regd. Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001. Website: http://www.indiabullsrealestate.com

Pennar Industries Limited Registered Office: Floor No. 3, DHFLVC Silicon Towers, Kondapur, Hyderabad - 500084 NOTICE TRANSFER OF EQUITY SHARES TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

BHARAT ELECTRONICS LIMITED (A Govt. of India Enterprise under the Ministry of Defence) NOTICE (for the attention of the Ordinary Shareholders of the Company) FINAL REMINDER Sub: Transfer of Ordinary Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF)

DCB BANK DCB BANK LIMITED (CIN:L99999MH1995PLC089008) Registered Office: 601 & 602, Peninsula Business Park, Tower A, 6th Floor, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Tel. No. (022) 66187000

Alkem Laboratories Limited (CIN: L00305MH1973PLC174201) Regd. Office : Alkem House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013. Tel. No: +91 22 3982 9999

BALRAMPUR CHINI MILLS LIMITED (CIN - L15421WB1975PLC030118) Registered Office: FMC Fortuna, 2nd Floor, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata- 700 020

POST BUYBACK PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR THE ATTENTION OF EQUITY SHAREHOLDERS/BENEFICIAL OWNERS OF EQUITY SHARES OF JAGRAN PRAKASHAN LIMITED

This public announcement (the "Post Buyback Public Announcement") is being made in compliance with Regulation 19(7) of the Securities and Exchange Board of India (Buy Back of Securities) Regulations, 1998, as amended (the "Buyback Regulations").

- 1. THE BUYBACK 1.1 Jagran Prakashan Limited (the "Company") had announced the Buyback of up to 155,00,000 (One hundred and fifty five lakh) (representing 4.74% of the total number of equity shares in the paid-up share capital of the Company) fully paid-up equity shares of face value of INR 2 (Indian Rupees Two) each ("Equity Shares")

Table with 6 columns: Category of Investor, No. of Equity Shares reserved in Buyback, No. of Valid Bids, Total equity Shares Validly Tended, % Response, No. of shares accepted to be bought back

- 2.5 All valid applications have been considered for the purpose of Acceptance in accordance with the Buyback Regulations and the Letter of Offer. The communication of acceptance/rejection shall be sent by the Registrar to respective Shareholders by Thursday, 20th April, 2017.

Table with 4 columns: Particulars, Pre Buyback (No. of Shares, Amount in ₹), Post Buyback (No. of Shares, Amount in ₹)

- 3.2 The details of the Shareholders/beneficial owners from whom Equity Shares exceeding 1% of the total Equity Shares bought back have been accepted for buyback in the Buyback Offer are mentioned below:

Table with 4 columns: Sr. No., Name of Shareholders, No. of Equity Shares accepted under the Buyback Offer, Equity shares accepted as a % of total Equity Shares bought back, Equity shares accepted as a % of total post Buyback Equity Shares of the Company

Table with 4 columns: Particulars, Pre Buyback (No. of Equity Shares, % of the existing equity share capital), Post Buyback (No. of Equity Shares, % of the post Buyback equity share capital)

- 4. MANAGER TO THE BUYBACK OFFER ICICI SECURITIES LIMITED ICICI Centre, H.T. Parekh Marg, Churchgate, Mumbai - 400 020, India

ಸಮಾಚಾರ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ

ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಮರುನಾಮಕರಣ

Morladu ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಮಠದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ...

ಸರ್ಕಾರಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಹೀಲ್ಸ್ ಮಠದ ಹೆಸರು...

ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫಫಾಂಟೋಗೆ ತಡೆ

Morladu: ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಫಫಾಂಟೋಗೆ ತಡೆ...

ಗಂಜಾ ಮಾರಾಟ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ಧನ

Morladu: ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗುರುನಿರ್ದೇಶನ ಹಾಗೂ...

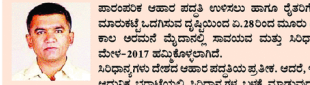
ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Morladu: 2017-18 ಸಾಲಿಗರ ಬಳಗ...

ಮೋಡಿ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ: ಕೃಷಿಬೆರಗೋಡೆ

ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...

ಎ.28ರಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ



ಮೋಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅ.28ರಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ...

ವಿರಾಟೆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ

ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...



ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜ್ಜಿಟ್ ವಸತಿ ಮತ್ತು...

ಗಾರ್ಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೇಟಿ

ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...

ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಜಾಗೃತಿ



ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...

ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಒಪ್ಪಂದವಿಲ್ಲ: ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಚಿಡಿಎಸ್ ಸಿದ್ಧ

ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...

224 ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳ



ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಜಯನಗರ ಬಹುಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ...

ಕರೆದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವೆ

ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...



ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವೆ...

ಚಿಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಭರವಸೆ | 120 ಶಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಮನವಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸಿಎಂ ಆದ್ರೆ ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ

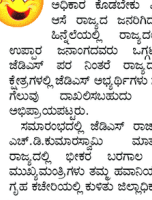
ನಿ ವಿತ್ತಭಾರತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂವಹನ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ...

ಟೆಸಲ್‌ರೋಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಎಚ್‌ಡಿಎಸ್ ವಿರೋಧ



ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅ.28ರಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ...

ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಸಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ...



ಪ್ರತಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಸಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರೆ...

ಸಿಸಿಮಾಸ್ಟರ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅ.28ರಂದು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ...

ಸಿಸಿಮಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ...

Advertisement for 'Sri Sanyasa' featuring a photograph of a man and promotional text.

Advertisement for 'Sri Sanyasa' with contact details and a list of services.

2 कंपनी समाचार

खबरों में रहे स्टॉक

जुड़ भारत मारुति

चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 72 फीसदी बढ़ा

₹ 435.85 पिछला बंद भाव
₹ 523.00 आज का बंद भाव
▲ 20.00%

काइटेक्स गारमेंट्स

बोनस प्रस्ताव पर विचार के लिए बोर्ड बैठक 28 अप्रैल को

₹ 427.60 पिछला बंद भाव
₹ 509.80 आज का बंद भाव
▲ 19.22%

फ्यूचर रिटेल

बोर्ड ने होम रिटेल कारोबार को अलग करने की मंजूरी दी

₹ 292.85 पिछला बंद भाव
₹ 305.90 आज का बंद भाव
▲ 4.46%

न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोटर्स

शेयर पुनर्संरीद मुद्दे पर विचार के लिए बोर्ड बैठक 25 अप्रैल को

₹ 260.25 पिछला बंद भाव
₹ 272.15 आज का बंद भाव
▲ 4.57%

एनबीसीसी (इंडिया)

वायदा एवं विकल्प श्रेणी में 28 अप्रैल से शामिल

₹ 181.75 पिछला बंद भाव
₹ 191.60 आज का बंद भाव
▲ 5.42%

संक्षेप में आयकर विभाग ने केयर्न से मांगा जुर्माना

आयकर विभाग ने ब्रिटेन की कंपनी केयर्न एनर्जी के खिलाफ एक नया नोटिस जारी कर 30,700 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है। कंपनी से यह जुर्माना उसके द्वारा 10,247 करोड़ रुपये के कथित पूंजीगत लाभ कर का समय पर भुगतान नहीं करने पर मांगा गया है। कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि आयकर विभाग ने पहले तो 10,247 करोड़ रुपये का नया मांग नोट भेजा जबकि उसके बाद एक कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि समय पर कर नहीं चुकाने तथा रिटर्न नहीं फाइल करने के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

सेंसेक्स नेक्स्ट 50 सूचकांक से हटेगी यूएसएल, केयर्न

यूनाइटेड स्प्रिट्स, केयर्न इंडिया को 26 अप्रैल से बीएसई के सेंसेक्स नेक्स्ट 50 सूचकांक से हटाया जा रहा है। बीएसई ने कहा है कि उक्त कंपनियों का जगह पेट्रोनेट एलएनजी व हैवेलस इंडिया को शामिल किया जाएगा।

ताज मानसिंह की होगी नीलामी

सर्वोच्च न्यायालय ने ताज मानसिंह की नीलामी के लिए एनडीएमसी को दी हरी झंडी

ताज ब्रांड के तहत होटलों का परिचालन करने वाली टाटा समूह की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी (आईएचसी) दिल्ली के लुटियंस क्षेत्र में 294 कमरों वाले लक्जरी होटल ताज मानसिंह पर अपना स्वामित्व बरकरार रखने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस क्षेत्र के शहरी निकाय नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए हरी झंडी दी। ताज मानसिंह की नीलामी के लिए एनडीएमसी कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इंडियन होटल्स ने कहा है कि वह नीलामी प्रक्रिया में भाग लेगी। इस खबर से माल्यु कंपनी का शेयर बंबई स्टॉक एक्सचेंज पर आज 123.80 रुपये के निचले स्तर तक लुढ़कने के बाद पिछले कारोबारी सत्र के बंद भाव के मुकाबले 1.33 फीसदी गिरावट के

आलीशान होटल की नीलामी



- नीलामी प्रक्रिया में भाग लेगी इंडियन होटल्स
- कंपनी का शेयर 1.33 फीसदी गिरावट के साथ 126 रुपये पर बंद हुआ
- इंडियन होटल्स इस संपत्ति के लिए पहले इनकार का अधिकार हासिल करना चाहती थी
- यह होटल 33 वर्ष के पड़े पर 1978 में खोला गया था

साथ 126 रुपये पर बंद हुआ। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा, ‘हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान

न्यायमूर्ति आरएन नरीमन के पीठ में लंबी सुनवाई के बावजूद कोई समझौता नहीं हो सका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं। वह एनडीएमसी के सदस्य भी हैं। होटल की अब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह हार हो चुकी है। इंडियन होटल्स इस संपत्ति के लिए पहले इनकार का अधिकार हासिल करना चाहती थी। हालांकि न्यायालय ने एनडीएमसी को उस दलील को स्वीकार किया कि कंपनी को पहले इनकार का अधिकार नहीं हो सकता। नीलामी प्रक्रिया में कंपनी यदि हार जाती है तो उसे होटल खाली करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि एनडीएमसी इस विशिष्ट संपत्ति की नीलामी करते समय टाटा समूह की कंपनी आईएचसीएल के बेदाग रिकॉर्ड को ध्यान में रखेगा। इससे पहले एनडीएमसी ने नीलामी प्रक्रिया के संचालन के लिए एसबीआई कैप से बात की थी।

वित्त वर्ष 2016 में इंडियन होटल्स के कुल 4,590 करोड़ रुपये के समेकित करीब 150 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। टाटा समूह की कंपनी इस संपत्ति में अपने इक्विटी निवेश के आधार पर लाइसेंस को नवीनीकृत करना चाहती थी।

विप्रो ने करीब 500 कर्मचारी निकाले

आयात प्रामाणिक बेंगलूर, 20 अप्रैल

भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर नियतक विप्रो ने अपनी मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत कई सौ कर्मचारियों को छंटनी कर दी है। गौरतलब है कि इस समय तकनीक सेवा उद्योग को स्वचालन और अपने प्रमुख बाजारों में संरक्षणवाद की दोहरी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। सुत्रों ने बताया कि करीब 500 कर्मचारियों को निकाले जाने का अनुमान है। विप्रो ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की, लेकिन यह कहा, ‘वह नियमित आधार पर कड़ी मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाती है ताकि वह अपने कर्मचारियों को कारोबारी उद्देश्यों, संगठन की रणनीतिक प्राथमिकताओं और अपने ग्राहकों की जरूरतों के मुताबिक बना सके।’

विप्रो ने एक बयान में कहा, ‘इस सुनियोजित और व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया के तहत परामर्श, फिर से प्रशिक्षण और कौशल विकास जैसे कदम उठाए जाते हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन में कुछ कर्मचारियों को कंपनी से हटाया



और सह-संस्थापक एनआर नारायणमूर्ति ने एक वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी को कंपनी से बाहर होने के एवज में इतनी बड़ी रकम के भुगतान पर सवाल उठाया था। टेकेलेजिग एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के मैनेजिंग पार्टनर सलमान वारिस ने कहा कि इस प्रकार के हार्ड-सेल्फ-हिल मामले में इस बात की संभावना अधिक है कि इन्फोसिस अदालत से बाहर समझौता कर ले। इस बाबत जानकारी के लिए फोन कॉल और मैसेज के जरिये बार-बार संपर्क किए जाने के बावजूद बंसल ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्फोसिस के सुत्रों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष इस मामले में मध्यस्थता का रुख किया है। इन्फोसिस के प्रवक्ता ने कहा, ‘कंपनी एक विस्तृत बयान के जरिये पूर्व सीएफओ राजीव बंसल के लिए कंपनी से बाहर होने के एवज में भुगतान पैकेज को पहले ही स्पष्ट कर चुकी है। फिलहाल इसमें जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ भी अतिरिक्त नहीं है।’ वारिस ने कहा, ‘यह साफ तौर पर एक ऐसा मामला दिख रहा है जहां कर्मचारी का पलड़ा भारी है। लेकिन यदि मध्यस्थता अदालत का फैसला कर्मचारी के पक्ष में जाता है तो इन्फोसिस उच्च न्यायालय का रुख भी कर सकती है जिससे समाधान में और देरी होगी।’

Indiabulls REAL ESTATE

इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड

(CIN: L45101DL2006PLC148314)

पंजीकृत कार्यालय : एम-62 एवं 63, पहली मंजिल, कर्नाट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001
फोन : 011-30252900 फैक्स : 011-30252901

वेबसाइट: <http://www.indiabullsmrealestate.com/> ई-मेल: helpdesk@indiabulls.com

सूचना

भारतीय प्रतिष्ठित और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसार एनूद्वारा सूचित किया जाता है कि मार्च 31, 2017 को समाप्त हुई तिमाही एवं वित्तिय वर्ष के लिए, **इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड** (कंपनी) के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृति हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, अप्रैल 27, 2017 को आयोजित की जायेगी।

कृपया अधिक जानकारी के लिए कंपनी की वेबसाइट (<http://www.indiabullsmrealestate.com/>) या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (<http://www.nseindia.com>) या बीएसई लिमिटेड (<http://www.bseindia.com>) पर सम्पर्क करें।

कृते इंडियाबुल्स रियल इस्टेट लिमिटेड

सही/रवि तेलकर
कंपनी सचिव

स्थान - मुंबई
दिनांक - अप्रैल 20, 2017

अनु. क्र.	कर्जदार (औ) का नाम और पता (ए/ए/के)	करी राशि (₹.)	गिरवी संपत्ति का विवरण (सी)	बकाया राशि (₹.)
1.	श्री/श्रीमती 1. अमरेंद्र शाह 2. सुनील शाह (उर्फ नीलेश शाह)	₹. 34,30,000/- (रुपये चौबीस लाख तीस हजार) के लिए, कर्ज खाता क्र. HHL.NO.00222886	संपत्ति है - बुकिंग डी-1703, सहवर्षी मंजिल, टावर/ब्लॉक-डी, न्यूटेक ला गेलेक्सिया, प्लॉट नं-11, सुरजपुर साइट सी, फेज-II, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305	₹. 34,06,966/- (रुपये चौबीस लाख छह हजार नौ की क्विन्टल मात्र) 11.04.2017 के अनुसार @ 10.75% प्रति बर्ष की दर से भावी ब्याज के साथ 12.04.2017 से प्रभावी शेकर भुगतान की वास्तविक तिथि तक.
	सभी: 48/9, निती विहार किकारी, सुलेमान नगर, नई दिल्ली - 110086.		(अधिक विस्तृत वर्णन अनुसूची-ए में दिया गया है)	
	साथ ही: C/O. मेर्सल शारदा एंटरप्राइजेस, पब्लिक नं 3514/2/2, नवीन एकाइ स्कूल के पास, मिटाडी गांव, नानोली, दिल्ली - 110086.			
	साथ ही: C/O. मेर्सल शारदा एंटरप्राइजेस, पब्लिक नं 3514/2/2, नवीन एकाइ स्कूल के पास, मिटाडी गांव, नानोली, दिल्ली - 110086.			
	संविद नं डी-1703, सहवर्षी मंजिल, टावर/ब्लॉक-डी, न्यूटेक ला गेलेक्सिया, प्लॉट नं एच आर ए-11, सुरजपुर साइट सी, फेज-II, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश-201305.			
	पञ्चागणकर्ता नं. 1			
	संविद नं 35/7/3, तनू मजिल, किकारी गांव, इंदर एएस्कन, फेज-1, नवीन एकाइ स्कूल के पास, दिल्ली - 110041.			

पावर गिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: 84, इंदिरा इन्टरनैशनल प्लाजा, कटोराबा बजार, नई दिल्ली-110016
फोन: 011-26561012, फैक्स: 011-26601081, CIN: L45101DL1989G003821

एमपी को. सेक्टर-43, गुडगांव के ऑडिटोरियम हेतु लॉ लूमिंग प्रोजेक्टवर की अपूर्ण तथा स्थापना के लिए बोलियों का आमंत्रण (आईएफबी) (एकल चरण दो सिफाफा बोली प्रणाली, फंडिंग: परतु)

दिनांक: 21.04.2017

पावरगिड द्वारा निम्नलिखित पैकेज हेतु mjunction के ई-पोर्टल <https://pgcileps.buyjunction.in> के माध्यम से ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

संस्थितिकेशन सं.	पैकेज संदर्भ	विवरण/स्थान	निविदा दर्स्तावेजों को डाउनलोड करने/निविदा प्रस्तावेज की लागत	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि सांठ प्रतियोगिता तथा शर्त प्रति भाग
सी/एमएम/एचआर-प्रशा./प्रोजेक्ट/331/2017	लॉग थो हाई लूमिंग प्रोजेक्टवर	गुडगांव	22.04.2017 से 21.05.2017 1500 बजे तक	29.05.2017 [1500 बजे]

1. निविदा कार्यक्रम में परिशिष्ट/संगोपन पर कोई हो सहीत अन्य विवरणों के लिए कृपया mjunction के प्रोग्रामरैट पोर्टल <https://pgcileps.buyjunction.in> पर जाए।

2. निविदा दर्स्तावेजों की लागत पावर गिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली / गुडगांव में देश डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 21.05.2017 को 15:00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से जमा की जाए।

3. निविदा का पहला सिफाफा (योग्यता आवश्यकता) जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात 29.05.2017 को 15:30 बजे के 30 मिनट बाद खोला जाएगा।

4. केवल संदर्भ के लिए संपूर्ण निविदा दर्स्तावेज हमारी वेबसाइट <http://www.powergridindia.com> पर भी उपलब्ध है। हालांकि, बोलीदाता अपनी बोलियों केवल mjunction के पोर्टल <https://pgcileps.buyjunction.in> पर ही अपलोड कर सकते हैं।

5. सभी संगोपन, निर्धारित तिथि विस्तारण, स्पष्टीकरण इत्यादि केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किए जाएंगे तथा समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वह स्वयं को अपडेट रखने के लिए उपरोक्त वेबसाइट निर्धारित रूप से देखते रहें।

6. निविदा दर्स्तावेजों की विक्री तथा निविदा जमा करने सहित सभी पञ्चावार/सूचना इस पत्र पर करें: एजीएम (एमएम)/प्रबंधक (एमएम), पावरगिड, ‘सौदागिनी’, तीसरा तल, प्लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, (हरियाणा) फोन नं. 0124-0124-2822323

विद्युत संबंधित शिकायतों हेतु 1912 डायल करें।

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(एक मालव के अर्धी भारत सरकार का एक उद्यम)

CIN: L32309KA1954QI000787

पंजीकृत कार्यालय, आर्ट डी रोड, नावारा, बेंगलूर - 560 045

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

(कंपनी के सामान्य शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

अंतिम अनुस्मारक

विवय - निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईपीएफ) में कंपनी के सामान्य शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों के लिए आईपीएफ प्राधिकरण को शेयरों के अंतरण के लिए बिजनेस स्टैंडर्ड एंड प्रेबुषाणी में प्रकाशित पहले नोटिस के संदर्भ में जिनके लाभांश को सातवें या उससे अधिक लातवार वषों तक अदत्त / अदावा के रूप में रखा गया है, यह सूचना दिनांक 28 फरवरी 2017 को प्रभावी कार्यावधि द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकार (लेखांकन, लेखा-परीक्षा, अंतरण और वापसी) नियमावली, 2016 (“आईपीएफ नियम”) के साथ पंक्ति पंक्तियों अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तारतम्य में पुनः प्रकाशित किया जाता है। अन्य विषयों के साथ आईपीएफ नियमों में लातार सात वर्षों से अधिक अवधि के लिए अदत्त या अदावा लाभांश आईपीएफ प्राधिकार के डीमैट खाते में अंतरित करने और अदत्त या अदावा लाभांश आईपीएफ को अंतरित करने का प्रावधान शामिल है। दिनांक 24.11.2016 तथा 19.04.2017 को क्रमशः कंपनी द्वारा वैयक्त सूचना एवं अंतिम अनुस्मारक उत्त संबंधित शेयरधारकों, जिनके पिछले सात वर्षों या उससे अधिक के लिए अदत्त / अदावा लाभांश रखे गए हैं, को उनके नवीनतम अउलभ्य पते पर भेजे गए थे तथा आईपीएफ प्राधिकार के डीमैट खाते में अंतरित किए जानेवाले संबंधित शेयरधारकों से निवृत्त कंपनी की वेबसाइट www.bel-india.com पर अपलोड किया गया है तथा शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वैयक्तिक <http://www.bel-india.com/ContentPage.aspx?MId17CId463LDId11nk463> का संदर्भ लें। संबंक्षित शेयरधारकों जो शेयर भौतिक रूप में रखते हैं और जिनके शेयर आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अदत्त किए जाने हेतु बाध्य है, यह अदत्त करें कि कंपनी उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले शेयर की सुविधित जारी की जाएगी और सुविधित शेयर प्रमाण पत्र जारी किए जाने पर उनके नाम पर पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र खर्च बंद हो जाएंगे और गैर-विक्रीय माना जाएगा। यदि शेयर डीमैट रूप में धारित हैं और आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अदत्त किए जाने हेतु बाध्य है, कंपनी आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित करने की निर्गत निवृत्त कार्यावधि/कार्य योजना के माध्यम से निष्पत्ति को सुचित किया जाएगा। संबंक्षित शेयरधारकों से निवेदन है कि वे 10 मई, 2017 या उससे पहले अपने अदावा / अदत्त लाभांश राशि का दावा करें। नवीनतम 10 मई, 2017 तक यदि कंपनी को शेयरधारकों से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो, आईपीएफ नियमों के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी, आईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खातों में शेयरों को बिना किसी संदर्भ के स्थानान्तरित करने हेतु आगे की प्रक्रिया करेगी। यह भी ध्यान दिया जाए कि आईपीएफ नियम के नियम 7 के साथ फंडनीय कंपनी अधिनियम, 2013 को धारा 124(6) के अनुसार आईपीएफ प्राधिकार के डीमैट खाते में अंतरित शेयरों की www.iiefp.gov.in पर उपलब्ध पत्र सं. आईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन कर दावा किया जा सकता है। कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त नियमों के तारतम्य में, कोई अदावा लाभांश तथा आईपीएफ प्राधिकरण के पक्ष में अंतरित शेयरों के संबंध में कंपनी के पास कोई दावा न हो। किसी दावे या पुनर्जात की स्थिति में शेयरधारक इस पत्र पर संपर्क करें - कंपनी रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स इंटिग्रेटेड रजिस्ट्री मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लि. 30, रमना रोड, नई दिल्ली, सिंगो रोड, मल्लेस्वरम, बेंगलूर - 560 003 दूरध्वनी: 080-23460815 से 818; फैक्स सं. 080-23460819 ई-मेल: irgintegratedindia.in

क्रेत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

हस्ताक्षर / एस श्रीनिवास कंपनी सचिव

स्थान: बेंगलूर दिनांक: 20 अप्रैल, 2017

अमेरिका में नियुक्ति पर टेक महिंद्रा का जोर

आयात प्रामाणिक बेंगलूर, 20 अप्रैल

सॉफ्टवेयर सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा अमेरिका में चुनौतियों से निपटने के लिए शिक्षण संस्थानों से स्थानीय इंजीनियरों की नियुक्ति पर जोर देगी। वीजा बांजीबे के मद्देनजर कंपनी ने यह रणनीति बनाई है ताकि उसे अपने ग्राहकों की परियोजनाओं पर काम करने के लिए इंजीनियरों की किल्लत जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। अमेरिका के एचबी वीजा नियमों में बदलाव की प्रक्रिया के बारे में वरिष्ठ अधिकारियों को बताते हुए कंपनी के मुख्य कार्यकारी एवं प्रबंध निदेशक सीपी गुरनानी ने कहा कि कंपनी अतिरिक्त से अधिक अमेरिकी कर्मियों को नियुक्त कर उन्हें उभरती प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने की पहल कर रही है। गुरनानी कहा, ‘टेक महिंद्रा शुरू से ही वैश्वीकरण का पक्षधर रही है और वह अपनी जरूरत के हिसाब से स्थानीय लोगों को नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण पर जोर देती रही है। अमेरिका के लिए हमारी एक विशेष कंपनी है और शिक्षण संस्थानों के साथ हमारी सहभागिता से हमें स्थानीय इंजीनियरों को नियुक्त करने में मदद मिलेगी।’ बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी गुरनानी के इस पत्र को देखा है।

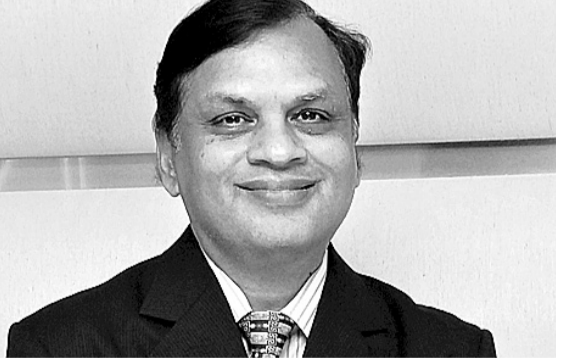
इन्फोसिस के साथ मध्यस्थता में बंसल का पलड़ा भारी: विश्लेषक

आयात प्रामाणिक बेंगलूर, 20 अप्रैल

कंपनी से बाहर होने के एवज में भुगतान के मामले में इन्फोसिस के साथ चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया में कंपनी के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी राजीव बंसल का पलड़ा भारी दिख रहा है। मानव संसाधन एवं कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले आमतौर पर कर्मचारी के पक्ष में जाते हैं क्योंकि न्यायालय और ट्रिब्यूनल उन्हें एक बड़ी कंपनी या संगठन के सामने पीड़ित मानते हैं। बंसल ने अपने बकायों के लिए कानूनी लड़ाई में मध्यस्थता के लिए लॉ फर्म इंडस लॉ को नियुक्त किया है जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रान को इस मामले में एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया है। इन्फोसिस ने अदालत में अपना रुख रखने के लिए निशीथ देसाई एसोसिएट्स का सहारा लिया है। सबसे पहले टाइम ऑफ इंडिया ने सुत्रों के हवाले से गुरुवार को यह खबर दी है। कंपनी और बंसल के बीच 17.38 करोड़ रुपये पर सहमति बनी थी जिसमें से इन्फोसिस ने उन्हें 5 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया और शेष रकम को लटका दिया। बंसल 2015 में कंपनी से बाहर हुए थे। कंपनी के संस्थापकों

वीडियोकॉन की चाहत, ऋण अवधि बढ़ाएं बैंक

देव चटर्जी
मुंबई, 20 अप्रैल



वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज ने अपने लेनदारों से ऋण की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया है ताकि कंपनी अपने बहीखाते पर नकदी प्रवाह और पुनर्भुगतान के बीच तात्कालिक अंतर को पाटने में समर्थ हो सके। कंपनी पर घरेलू बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

गुप चेरमैन वेणुगोपाल धूत ने कहा कि विदेश में कंपनी के पास आकर्षक तेल एवं गैर पेरिसंपत्तियां मौजूद हैं लेकिन फिलहाल वह अपने दूरसंचार कारोबार में नकदी प्रवाह की समस्या से जूझ रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2012 में स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द किए जाने के बाद समूह को अपने दूरसंचार कारोबार में कथित तौर पर करीब 25,000 करोड़ रुपये का घाटा हो चुका है। उन्होंने कहा, ‘पिछले छह वर्षों के दौरान हमने ब्याज के रूप में बैंकों को करीब 26,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। लेकिन अब हम बैंकों से ऋण की अवधि बढ़ाने का आग्रह कर रहे हैं।’

का बाजार पूंजीकरण आज दोगुना से अधिक बढ़ कर 13,186 करोड़ रुपये हो चुका है। जबकि निजी इक्विटी कंपनियों ने अधिग्रहण के उसका मूल्यांकन 5,000 करोड़ रुपये आंका था। धूत ने कहा कि ऋण की अदायगी के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, ‘बैंकों के साथ हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है और उन्होंने अब तक हमारी विकास यात्रा में साथ दिया है। हम ऋण अदायगी सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे।’

गुप चेरमैन देव चटर्जी ने कहा कि बैंक की पुष्टि की कि वीडियोकॉन ऋण की अवधि बढ़ाने के लिए बातचीत कर रही है। धूत ने कहा कि बिजली एवं कोयला क्षेत्र की अटकों परियोजनाओं में कंपनी की काफी रकम फंस गई है। उन्होंने कहा, ‘मध्य प्रदेश में हमारे पास 1,500 एकड़ और रायपुर एवं छत्तीसगढ़ में 200 एकड़ भूमि है जो सभी बुनियादी ढांचे से संबंधित है। इन सभी अटकों परियोजनाओं में काफी रकम फंस गई है। हम इन परियोजनाओं से बाहर निकलने के बारे में विचार कर रहे हैं।’

■ **समूह सामान्य बीमा कंपनी** में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा

■ **कंपनी के पास 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की रियल एस्टेट परिसंपत्ति**

मूख्यालय 300 करोड़ रुपये में बेचने के अलावा समूह सामान्य बीमा कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 5,000 करोड़ रुपये में बेचने की योजना बना रहा है। धूत ने कहा, ‘हमारे पास 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की रियल एस्टेट परिसंपत्ति है जो घरेलू ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक सौदे के तहत अपने विक्री की प्रक्रिया में है। केनस्टार ब्रांड की विक्री में निजी इक्विटी सहित कम से कम 20 खिलाड़ियों ने दिलचस्पी दिखाई थी। केनस्टार की प्रमुख प्रतिस्पर्धी क्रॉफ्टन ग्रिक्स कंच्यूर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

फोटो: (NITCS)HMMINT/6A97/17-18 Intrafile